

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (ङ) एक विवरण पत्र संलग्न है।

#### विवरण

चालू वर्ष में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने की व्यवस्था की गई है। देश में कुल मिलाकर उर्वरकों की बर्तमान होने की संभावना नहीं है। जहाँ तक पोष्टिक उर्वरक का संबंध है, हम पूर्णतया आयातों पर निर्भर हैं, क्योंकि यह अपने देश में उपलब्ध नहीं है। हम कच्चे माल, मध्यवर्ती तथा तैयार उर्वरकों के रूप में फास्फेटिक उर्वरकों के आयात पर गंभीर रूप से निर्भर हैं। वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में यूरिया, जो कि नाइट्रोजन का एक प्रमुख स्रोत है, का आयात नहीं किया गया है, क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता मुख्यतः स्वदेशी स्रोतों द्वारा पूरी की जा रही है।

#### दुग्ध उत्पादन

254. श्री बलराम सिंह यादव :

डा० जिनेंद्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दुग्ध के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो 1951 में देश में दुग्ध का उत्पादन कुल कितना था और वर्ष 1990 के दौरान दुग्ध का उत्पादन कितना रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दुग्ध की अधिकांश मात्रा विक्री हेतु शहरी क्षेत्रों में भेज दी जाती है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की दुग्ध खरीदने की क्षमता बहुत कम है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने दुग्ध की उत्पादन लागत कम करने के साथ-साथ इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई शिक्षाप्रद उपाय किए हैं जिससे कि ग्रामीण लोगों की दुग्ध खरीदने की क्षमता बढ़ाई जा सके और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1989-90 में अनुमानित अन्तिम दुग्ध उत्पादन 52.4 मिलियन टन था, जबकि 1951 में यह 17.4 मिलियन टन था।

(ग) दुग्ध उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है और दुग्ध उत्पादक उपाजन अथवा पुरक आमदनी प्राप्त करने के लिए अपना अतिरिक्त दुग्ध अन्य कृषि उत्पादों की तरह, शहरी बाजारों में बेचते हैं। दुग्ध उत्पादन का वितरण देश में असमान है और एक क्षेत्र में उत्पादित दुग्ध की अतिरिक्त मात्रा बाजारों के विभिन्न चैनलों के जरिये कर्म वाले क्षेत्रों में पहुँचती है।

(घ) ग्रामीणों की क्रय शक्ति शहरी लोगों की तुलना में सामान्यतया कम होती है। प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध की औसत खपत भिन्न-भिन्न होती है जो दुग्ध के स्थानीय उत्पादन, भोजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 42वें सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवार अपने भोजन व्यय का 14.5 प्रतिशत अथवा कुल उपभोक्ता व्यय का 9.5 प्रतिशत दुग्ध अथवा दुग्ध उत्पादों पर व्यय करते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ये आंकड़े क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 10.0 प्रतिशत हैं।

(ङ) दुग्ध की उत्पादन लागत को कम करने के लिए आपरेशन प्लड के अंतर्गत कई कदम उठाए गए हैं जैसे दुग्धारू पशुओं में इन्जिन गर्भाधान करके आनुवंशिक सुधार के केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यक्रम, संतुलित पशु आहार

का उत्पादन, खतरनाक रोगों के लिए टीकाकरण तथा पशु स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान।

### सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आबंटन

255. श्री बलराम सिंह यादव :

डा० जिनेंद्र कुमार जैन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सहकारी सामूहिक आवास समितियों को पपन कला और नरेला में भूमि आबंटित किए जाने के संबंध में पत्र जारी कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो नवम्बर, 1990 के अन्त तक कितनी सहकारी सामूहिक आवास समितियों को पत्र जारी किए जा चुके हैं ;

(ग) क्या पत्र जारी करते समय "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर सहकारी सामूहिक समितियों की कोई प्राथमिकता सूची तैयार की गई थी और क्या उक्त सूची आम जनता के लिए प्रकाशित की गई थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) पंजीयक, सहकारी समितियों द्वारा यथोचित सत्यापन के पश्चात् तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी किए गए हैं। नवम्बर, 1990 के अन्त तक पंजीयक, सहकारी समितियों, ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को 414 समितियों की सूची प्रस्तुत की है। चूंकि उन सभी 414 समितियों को प्रस्ताव पत्र अलग-अलग भेजे गए थे इसलिए, अलग से कोई सूची

प्रकाशित करने आवश्यक नहीं समझा गया था। यह भी बताया जाता है कि 9 और समितियों को प्रस्ताव पत्र दिए गए हैं जिससे समितियों की कुल संख्या बढ़कर अब 423 हो गई है।

### Steps to check oil erosion

256. SHRI BAL\* RAM SINGH  
YADAVA:

DR. JINENDRA KUMAR  
JAIN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item under the caption '5,000 mt. P.A. of soil being lost due to erosion' published in the 'Financial Express' dated the 12th December, 1990;

(b) if so, whether it is also a fact that vast fertile land is becoming saline in several States because of non utilization of proper manure and for want of proper care;

(c) if so, whether Government have taken any necessary action to check the same and also to retrieve the saline land; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHANDBHAI SHAH): (a) Yes, Sir.

(b) Factors\* generally responsible for salinity in soils are:—

(i) indiscriminate use of canal water;

(ii) capillary rise from subsoil bed of salts;

(iii) weathering of rocks and the salts brought down from the up-